

R 597-1108

Rs 15/-

न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 12000 पुनरीक्षण.

प्यारैलाल पुत्र श्री घसीटे, आयु 60 वर्ष,
निवासी ग्राम सुकवा, तैहसील व जिला
हृत्तरपुर म०प्र० --- आक्षेपक.
वनाम.

१) मथुरा पुत्र श्री हलकाई काकी, आयु 55 वर्ष,
निवासी ग्राम सुकवा, तैहसील व जिला
हृत्तरपुर म०प्र० --- आक्षेपक.

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 40 म०प्र० मू-राजस्व संहिता,
विरुद्ध आदेश दि० ७-११-०७ पारित द्वारा श्रीमान्
अपर आयुक्त सागर संभाग सागर, प्रकरण क्रमांक 39अ।१
X 06-07 वतनवान प्यारैलाल वनाम मथुरा

माननीय महोदय,

आक्षेपक की ओर से पुनरीक्षण निम्नलिखित प्रस्तुत है-

संक्षिप्त तथ्य :

(अ) यहकि, प्रकरण में विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 3288A।
रकवा ७-५० एकड़ भूमि स्थित ग्राम सुकवा, तैहसील व जिला
हृत्तरपुर पर आक्षेपक अपनी पूर्वजों के समय से निर्विवाद रूप से काविज
होकर कृषि करता चला आ रहा है। जो कि म०प्र० मू-राजस्व
१९५६ लागू होने के पूर्व १९४६-४७ से कृषि कर अपना व अपने परिवार
का भरण पोषण करता चला आ रहा है और शासकीय अभिलेख में
नाम अंकित था। जिसे बिना किसी सच्चे अधिकारी के आदेश के
आक्षेपक का नाम निरस्त कर दिया। आक्षेपक को जानकारी होने पर

नोट I

श्री
द्वारा आज दि० 26/05/08 को परसुवा
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

Submited
26/5/08

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

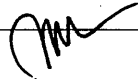
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 597-एक/2008

जिला-छतरपुर

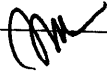
स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिषेक आदि के हस्ताक्षर
6-1-17	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 श्रीवास्तव उपस्थित. अनावेदक की और से अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित. यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग, द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 37/2006-07 में पारित आदेश दिनांक 7-11-2007 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा -50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है.</p> <p>2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैकि आवेदकगण द्वारा भूमि सर्वे क्रमांक 3149/5 रकबा 7.50 एकड स्थित ग्राम सुकवा पर अपने पिता, दादा, परदादा के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि होने तथा पिछले 100 वर्षों से अधिक समय से आधिपत्यधारी होने के कारण भूमि स्वामी घोषित करने के लिये उपबन्दोबस्त अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे उपबन्दोबस्त अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया. उप बन्दोबस्त अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अनावेदक मथुरा द्वारा अपर कलेक्टर जिला- छतरपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जो दिनांक 30-7-2007 को स्वीकार की जा रही उप बन्दोबस्त अधिकारी के आदेश दिनांक 23-12-1990 को</p>	





निरस्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि ग्राम- सुकवा की भूमि सर्वे क्रमांक 3149/5 रकबा 2.045 हेक्टेयर पूर्ववत मध्यप्रदेश शासन कदीम चरनोई रिकार्ड में अमल कराई जाये तथा भूमि सर्वे क्रमांक 3149/5 रकबा 1.21 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में हितबद्ध पक्षकारों को समुचित सुनवायी के पश्चात दस्तावेजी साक्ष्य के उपरान्त प्रकरण का निराकरण करे. प्रकरण प्रत्यावर्तन के पश्चात अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर द्वारा सुनवायी करने के उपरान्त अपने आदेश दिनांक 14-08-2006 के द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त किया गया उक्त आदेश के विरुद्ध आवेदकगण की ओर से अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जो उनके द्वारा अपने आदेश दिनांक 7-11-2007 के द्वारा निरस्त की गयी. उक्त आदेश के विरुद्ध आवेदकगण के द्वारा यह निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है.

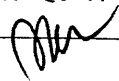
3. उभय पक्षों के अभिभाषकों के तर्कों को श्रवण किया गया. आवेदक गण के अभिभाषक द्वारा निगरानी में वर्णित आधारों पर ही जोर दिया गया तथा वर्तमान निगरानी आवेदन पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया. अनावेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में निवेदन किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण में सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना






करने के उपरान्त आदेश पारित किया गया है जो कि विधि सम्मत है. आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी जो कि प्रचलन योग्य ही नहीं थी. अपर आयुक्त ने सम्पूर्ण तथ्यों पर विचार करने के उपरान्त ही आवेदकगण की अपील को निरस्त किया गया था इस कारण से भी उपरोक्त आदेश अधिनस्थ न्यायालयों के आदेश उचित होने से निगरानी आवेदन पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया.

4. उभय पक्षों के तर्कों एवं प्राप्त अभिलेखों का मेरे द्वारा मनन किया गया. उपरोक्त के परिशिलन से मे यह पाता हूँ कि उप बन्दोस्त अधिकारी के आदेश को अपर कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा अपने आदेश द्वारा विस्तृत जाँच करने के उपरान्त निरस्त किया गया था तथा भूमि को शासकीय अंकित करने के निर्देश दिये गये थे उक्त आदेश को आवेदकगण की और से कोई चुनौती नहीं दी गयी. अपर कलेक्टर के आदेश के पश्चात शेष बचे भाग के सम्बन्ध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उभय पक्ष को सुनने के पश्चात तथा उनके समक्ष उपलब्ध अभिलेख के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदकगण के आवेदन पत्र को निरस्त किया गया था. अपर आयुक्त ने भी सम्पूर्ण तथ्यों पर विचार करने के उपरान्त उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को निरस्त किया गया है. प्रकरण के अभिलेख के अवलोकन



से यह भी पाता हूँ कि आवेदकगण की ओर से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष संहिता की धारा -57 (2) के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे उनके द्वारा निरस्त किया गया है. अतः 57(2) के अन्तर्गत पारित आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील कलेक्टर के समक्ष की जाना चाहिये थी ऐसा न करके सीधे अपर आयुक्त सागर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी इस प्रकार से भी आवेदक किसी प्रकार की राहत पाने का कोई अधिकारी नहीं है. अतः मैं उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में यह निगरानी आवेदन पत्र में किसी प्रकार कोई बल न होने से तथा अधिनस्थ न्यायालयों की कार्यवाही एवं किसी प्रकार की कोई अनियमितता न होना पाता हूँ.

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी अस्वीकार की जाती है. अधिनस्थ अपर आयुक्त सागर एवं अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के आदेश स्थिर रखे जाते हैं. उभय पक्ष सूचित हो. अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति संलग्न कर वापस किया जाये. तथा प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो.


सदस्य

